गहलोत के बनाये नौ जिले, 3 संभाग निरस्त

कैबिनेट ने माना, पूर्ववर्ती सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ के लिये निर्णय लिया था

- **आचार संहिता लगने से ठीक पहले तीन जिले और बनाने का कांग्रेस सरकार का निर्णय भी निरस्त किया।**
- **अब प्रदेश में 7 संभाग और 41 जिले होंगे। परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जायेगा।**

जयपुर, 28 दिसम्बर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाये गये नये जिलों में से नौ जिलों एवं तीन नये संभागों को निरस्त करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने पिछली सरकार के समय में गठित जिलों और संभागों का पुन: निर्धारण किया है, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल सात संभाग और 41 जिले होंगे।

पटेल ने बताया कि गत सरकार के इस अविवेकपूर्ण निर्णय की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति और इसके सहयोग के लिए सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. ललित के. पंवार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति द्वारा नवगठित जिलों एवं संभागों के पुनर्निर्धारण के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट एवं सिफारिशें मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की गईं।

समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार करते हुए, नए सृजित जिलों में नौ जिले, अनूपगढ़, दूदू, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर एवं शाहपुरा तथा नवसृजित तीन संभागों बांसवाड़ा, पाली, सीकर को नहीं रखने का निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया है।

उन्होंने बताया कि बैठक में आचार संहिता से ठीक पहले घोषित तीन नए जिलों, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को भी निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

पटेल ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में प्रदेश में 17 नवीन जिले एवं 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया था, तथा राजस्व विभाग द्वारा पांच अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर जिलों एवं संभागों का सृजन किया गया था। तीन नए जिलों की घोषणा विधानसभा चुनाव-2023 की आचार संहिता से एक दिन पहले की गई, जिनकी अधिसूचना भी जारी नहीं हो सकी थी।

उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने नवीन जिलों एवं संभागों का गठन पूरी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया। इसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक आवश्यकता, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक सामंजस्य आदि किसी भी महत्वपूर्ण बिन्दु को ध्यान में नहीं रखा गया। नए जिलों के लिए पिछली सरकार ने कार्यालयों में न तो आवश्यक पद सृजित किए और न ही कार्यालय भवन बनवाए। बजट एवं अन्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं कराई गईं।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल द्वारा यथावत् रखे गए आठ नए जिलों, फलौदी, बालोतरा, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन और सलूम्बर में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी वित्तीय संसाधन एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। इससे इन नए जिलों में रहने वाले आमजन को इन जिलों के गठन का लाभ वास्तविक रूप में मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि अब जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा संभाग के विधायकों के साथ पिछले बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन व आगामी बजट की तैयारी बैठक ली। उन्होंने प्रत्येक विधायक से उनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं के कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।

'विधायक बजट घोषणा के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कोटा संभाग के विधायकों को जनता के भरोसे पर खरा उतरने को कहा

- **मुख्यमंत्री ने विधायकों से आग्रह किया कि अपने क्षेत्र के जनहित के कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाकर भेजें ताकि उन कार्यों को बजट में शामिल किया जा सके।**

जयपुर, 28 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास और प्रदेशवासियों का कल्याण ही राज्य सरकार का एकमात्र ध्येय है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस ध्येय की पूर्ति में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अहम भूमिका है इसलिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में विधायकों को समर्पण भाव के साथ जनहित के कार्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए।

शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोटा संभाग के विधायकों के साथ पिछले बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन और आगामी बजट की तैयारियों से संबंधित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक विधायक को उसके विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ चुनकर भेजती है, ऐसे में जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह जनता के भरोसे पर खरा उतरे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रत्येक विधायक से उनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं के कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले बजट में राज्य के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को ढेरों सौगातें दी हैं और यह आवश्यक है कि आगामी बजट से पूर्व पिछले बजट में की गई घोषणाओं का धरातल पर उतरना सुनिश्चित हो। शर्मा ने कहा कि विधायकगण अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधायकों के साथ समन्वय बनाकर आधारभूत विकास के कार्यों में वित्तीय स्वीकृति से लेकर जमीन आवंटन, डीपीआर तैयार होने और निर्माण कार्य प्रारंभ होने तक प्रत्येक चरण पर समयबद्ध रूप से कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने दूरगामी सोच के साथ पिछला बजट प्रस्तुत किया था, जिसकी हर तरफ सराहना हुई। उन्होंने कहा कि आगामी बजट को भी राज्य की जनता के लिए सार्थक और समावेशी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनहित से जुड़े कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाकर भेजें, ताकि उन कार्यों को आगामी बजट में शामिल किया जा सके।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, संदीप शर्मा, कालूराम, कंवरलाल, राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा, कल्पना देवी, गोविंद प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दक्षिण तिब्बत पर प्रस्तावित...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की योजना है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम भारत की पूर्व स्वीकृत अधिकारों को स्थापित करने और क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के प्रयासों की रणनीति को दिखाता है।

भारत और चीन के सम्बंध पहले से ही नाज़ुक मोड़ पर है, इस समय बांध निर्माण को मंजूरी दी गई है। दोनों देशों के नेताओं की मीटिंग में 2020 के सीमा संघर्ष से उपजे तनाव को कम करने की उम्मीद जगी थी। यह मैगाडैम परियोजनाएं इन कूटनीतिक प्रयासों को कमज़ोर कर सकती हैं।

चीन के सुरक्षा विश्लेषक नीलैक्सियॉग ने कहा, बीजिंग इस बांध को घरेलू पहल मानता है, पर नई दिल्ली पर इसके प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यह प्रोजैक्ट चीन की जिओ पॉलिटिकल ताकत को बढ़ा सकता है। इस प्रोजैक्ट के जरिए भारत से निपटने में चीन जलीय मुद्दों को हथियार बना कता है। इस समय बांग्लादेश से भी भारत के सम्बंध तनावपूर्ण है और बांग्लादेश भी अपनी जरुरतों के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी पर आश्रित है। दोनों देशो ने बांध निर्माण पर चिंता जताई और कहा कि इससे नदी का प्रवाह बाधित हो सकता है और आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

जलविद्युत क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने की चीन की कोशिश उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए वह अपनी तकनीकी क्षमता और आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। पर इसकी कीमत उसे क्षेत्रीय भरोसे से चुकानी पड़ सकती है।

युनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट आफ पीस ने 2022 में एक रिपोर्ट में कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर जल विवाद बढ़ रहे हैं, जो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं को प्रभावित कर रहे है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन और भारत दोनों ही बांध निर्माण का हिमालय सीमा पर अपना दावा मजबूत करने का जरिया मानते है।

यह बांध भारत और चीन के बीच भरोसे की कमी को दर्शाता है। चीनी विशेषज्ञ लियू जोन्गयी ने कहा दोनों देश आपस में विश्वास नहीं करते, यह जगजाहिर है। यह प्रोजैक्ट दरार को और बढ़ाएगा या सहयोग के रास्ते खोलेगा, यह तो भविष्य ही बताएगा, पर इतना तय है कि इससे पर्यावरण प्रभावित होगा।

डल्लेवाल पर पंजाब के जवाब से सुप्रीम कोर्ट नाराज

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने कृषि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा खनौरी सीमा पर एक माह से अधिक समय से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे 70 वर्षीय किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की चिकित्सा संबंधी मामले से निपटने में पंजाब सरकार के जबाव से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए शनिवार को उसे फिर कड़ी फटकार लगाई तथा जवाब के लिए एक और मौका दिया। पीठ ने दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने में विफल रहने पर पंजाब सरकार को फिर कड़ी फटकार लगाई।

राज्यपाल ने केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर जांच के आदेश दिये

- **आप पार्टी ने घोषणा की थी कि दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे, जो 2025 में जीतने के बाद 2100 रुपये कर दिये जायेंगे।**

नई दिल्ली, 28 दिसंबर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान योजना विवादों में फंस गई है। कांग्रेस और भाजपा ने इस योजना पर पहले ही सवाल खड़े किए थे। वहीं, दिल्ली के अफसरों ने भी अखबार में विज्ञापन देकर कहा था कि दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। अब दिल्ली के गर्वनर वीके सक्सेना ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि इस योजना के तहत 18 साल से ऊपर की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। अगर 2025 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो यह रकम 1000 से बढ़ कर 2100 कर दी जाएगी।

दिल्ली के एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में आम आदमी पार्टी की उपरोक्त घोषणाओं के बारे में बताया गया है।

अरविंद केजरीवाल ने जांच के आदेश जारी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर आरोप लगाए और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा "कुछ दिन पहले हमने ऐलान किया था कि महिला सम्मान योजना में 2100 रुपये हर महीने देंगे। कैबिनेट ने 1000 देने की योजना पास की थी। दूसरी योजना बुजुर्गों को फ्री में इलाज देने की थी। इन दोनों योजनाओं से भाजपा की नींद उड़ गई। उनको लग गया कि चुनाव हार गए। पहले गुंडे भेजकर कैम्प हटाने की कोशिश की और अब जांच के आदेश देंगे। किस बात की जांच करेंगे।आज इन लोगों ने अपने इस कदम से बता दिया कि बीजेपी के चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है। महिला सम्मान योजना, बुजुर्गों की स्वास्थ्य योजना, फ्री बिजली-पानी सब बंदकरना चाहते हैं।आज बीजेपी ने एक हिंट दिया कि वो अगर जीत गए तो सारी योजना बंद करा देंगे।

पत्र में कहा गया है कि एलजी ने मुख्य सचिव से गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में संभागीय आयुक्त के माध्यम से जांच कराने को कहा है। इसके अलावा, पुलिस आयुक्त फील्ड अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें,जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

सोमवार को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का 'टारगेट' (लक्ष्य) होगा। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को यहां बताया कि इसरो का 30 दिसंबर को निर्धारित वर्ष के अंत का मिशन ऐतिहासिक होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को डॉक करने या विलय करने या एक साथ जोड़ने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने की कोशिश की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 'स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट' (स्पाडेक्स) नाम दिया गया है। अब तक इस काम में केवल अमेरिका, रूस और चीन को महारत प्राप्त है।

रुसी हवाई क्षेत्र में प्लेन क्रैश पर पुतिन ने माफी मांगी

- **अजरबैजानी विमान कजाकिस्तान में क्रैश हो गया था जिसमें 38 लोग मारे गये थे तथा 29 घायल हुए थे।**

मॉस्को, 28 दिसंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कज़ाकिस्तान में हुए प्लेन क्रैश मामले को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने अजरबैजानी विमान हादसे की त्रासदपूर्ण घटना के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति से माफी मांगी। दरअसल, इस विमान ने बुधवार को अजरबैजान की राजधानी बाकू से चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद इसका मार्ग परिवर्तित कर दिया गया और कज़ाकिस्तान में उतरने का प्रयास करते हुए विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए।

शनिवार को एक आधिकारिक बयान में रूसी राष्ट्रपति कार्यालय 'क्रेमलिन' ने कहा कि बुधवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण ग्रोज्नी के निकट वायु रक्षा प्रणालियों ने गोलीबारी की। हालांकि यह कहने से परहेज किया कि विमान रूसी वायु रक्षा प्रणाली की गोलीबारी का निशाना बना। क्रेमलिन ने रूस के राष्ट्रपति और अजरबैजान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई वार्ता के विवरण का हवाला देते हुए बताया कि पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से "इस तथ्य के लिए माफी मांगी कि यह दुखद घटना रूसी हवाई क्षेत्र में हुई।"

बता दें कि कजाकिस्तान में अजरबैजान का प्लैन क्रैश हो गया था, जिसमें 67 यात्री सवार थे। प्लैन क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे में 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। अजरबैजान के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने एक बयान में बताया कि देश के जांचकर्ता दुर्घटना की जांच के हिस्से के रूप में ग्रोजनी में काम में जुटे हैं। दुर्घटना की आधिकारिक जांच शुरू होने पर कुछ विमानन विशेषज्ञों ने बताया कि विमान के पिछले हिस्से में देखे गए छेदों से पता चलता है कि यह यूक्रेनी ड्रोन हमले से बचने के लिए रूसी वायु रक्षा प्रणाली के जवाबी हमले का शिकार हुआ होगा।

जैसलमेर : अचानक जमीन फटने पर वेग से पानी निकला

पानी के साथ गैस और कीचड़ आने लगा तो कर्मचारी व ग्रामीण दूर भाग गये

- **मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में ट्यूबवैल की खुदाई के समय जमीन धंसने से 22 टन वजनी मशीन लगा ट्रक 850 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया।**
- **ओ.एन.जी.सी. के अधिकारियों की टीम मौके का निरीक्षण करने आयेगी। अभी घटना स्थल से 500 मीटर की परिधि में पशुधन व आमजन का आना-जाना बंद करवा दिया गया है।**

जैसलमेर, 28 दिसम्बर (निसं), जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक एक ट्रक 850 फीट गहरे गड्ढे में धंस गया, जिस पर 22 टन की ड्रिलिंग मशीन फिट थी। ट्रक धंसने के साथ ही गड्ढे से ऊँचे फव्वारे की तरह पानी बाहर आने लगा। पानी के साथ गैस और कीचड़ भी बाहर आने लगा, जिसे देख कर दहशत में आए ट्यूबवेल की खुदाई कर रहे कर्मचारी और ग्रामीण वहां से दूर भाग गए।

जानकारी के अनुसार, हादसा शनिवार को चक 27 बीडी के तीन जोरा माइनर के पास विक्रमसिंह के खेत में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान सुबह 10 बजे हुआ। लोगों ने भूजल विभाग को इसकी जानकारी दी। भूजल वैज्ञानिक एनडी इनखिया, पुलिस तथा प्रशासन अपनी-अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे।

एनडी इनखिया ने बताया कि विक्रम सिंह के खेत में दो दिन से ट्यूबवेल की खुदाई चल रही थी, जिसके दौरान गड्ढे में ट्रक धंस जाने पर करीब 850 फीट की गहराई से पानी निकलने लगा। पानी का वेग इतना तेज था कि वहां गड्डा हो गया और तेज गति से पानी जमीन से बाहर आने लगा। इस दौरान खुदाई की मशीन ट्रक समेत जमीन में धंस गई।

उप तहसीदार ललित चारण का कहना है, गड्ढे से गैस निकली है, जिसकी वजह से पानी उछल रहा है। अगर ट्रक को हटाया गया तो गैस का रिसाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल आम सूचना जारी कर स्थान को खाली करवाकर वहाँ अस्थायी पुलिस चौकी लगाई जा रही है। तेल गैस कम्पनी ओएनजीसी के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, ताकि उनकी टीम मौके पर आए तो कुछ पता चले और समस्या का कुछ समाधान निकले। जानकारी के अनुसार, मौके पर गैस की बदबू आ रही है। गड्ढे में ट्रक फंसा है और गड्ढे से कीचड़, पानी और गैस निकल रही है। घटनास्थल से 500 मीटर की परिधि में पशुधन एवं आमजन का आना-जाना बंद करवा दिया गया है।

तालिबान ने हमला कर 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे

- **अफगानिस्तान ने कहा गत सप्ताह उन पर हुए घातक हवाई हमलों का जवाब दिया है।**

काबुल, 28 दिसंबर । बीते मंगलवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर पलटवार किया है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय की ओर से इस पलटवार के बारे में जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि तीन अफगान नागिरकों के भी मारे जाने की सूचना है। अफगानिस्तान ने ये हमला पाकिस्तान के कई इलाकों में किया है।

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसके बलों ने पिछले हफ्ते देश पर हुए घातक हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान के अंदर कई स्थानों पर हमला किया। मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान के हवाई हमलों में कई लोग मारे गए।

'सरकार ने डॉ. मनमोहन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस ने माँग की थी कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर कराया जाये, जहाँ उनका स्मारक बनाया जा सके।

जयराम रमेश ने शुक्रवार को "एक्स" पर पोस्ट किया, "आज सुबह, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अन्त्येष्टि ऐसे स्थान पर की जाये, जहाँ उनका स्मारक बन सके और लोग उनकी विरासत का सम्मान कर सकें। हमारे देश के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत सरकार को उनके अंतिम संस्कार तथा स्मारक के लिये आखिर कोई ऐसी जगह क्यों नहीं मिल सकी, जो उनके वैश्विक कद, विशिष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड तथा दशकों तक की गई देश की अनुकरणीय सेवा के अनुरूप एवं उपयुक्त हो।

यह और कुछ नहीं, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का जानबूझ कर किया गया अपमान है।

शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा सिंह के परिवार को सूचित किया था कि सरकार स्मारक के लिये बाद में स्थान आवंटित करेगी।

बढ़ती उम्र और उससे जुड़ी बीमारियों के कारण डॉ. सिंह लम्बे समय तक अवस्थ थे। 92 वर्ष की उम्र में गुरुवार रात दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम साँस ली।

आज निगम बोध घाट पर उनकी अन्त्येष्टि पूरे सैन्य सम्मान एवं राजकीय सम्मान के साथ की गई।

ग्राम विकास...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर निर्माण कार्यों, सिंगल फेज ट्ययूबवेल एवं हैडपंप लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। सभी निर्माण कार्य वार्षिक योजना के अनुसार ही करवाए हैं।

इन कामों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंचायत समिति पावटा एवं जिला परिषद जयपुर ने जारी की है। इसमें याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं है और यह निर्माण कार्य जनहित में करवाए हैं।

इसलिए याचिकाकर्ता से की जाने वाली रिकवरी को रद्द किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

पूर्ण सैन्य...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रृद्धांजलि दी। डॉ. सिंह की पत्नी, गुरशरण कौर तथा उनकी एक बेटी ने डॉ. सिंह की देह पर पुष्पचक्र अर्पित करके श्रृद्धांजलि दी। कांग्रेस, जिसने अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने की माँग की थी, जहाँ डॉ. सिंह का स्मारक बनवाया जा सके, ने इसे "भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझ कर किया गया अपमान" बताया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, मंत्रिमंडल की मीटिंग के तुरन्त बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सूचित कर दिया था कि सरकार स्मारक के लिये स्थान आवंटित करेगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में, पूरे देश में सात दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा तथा इस अवधि में, पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा।

अजित पवार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

छतरपुर से नरेन्द्र तंवर, लक्ष्मी नगर से नमहा, गोकुलपुरी से जगदीश भगत, मंगोलपुरी से खेम चंद, सीमापुरी से राजेश लोहिया और संगम विहार से कमर अहमद को प्रत्याशी बनाया है।

'डॉ. मनमोहन सिंह के जीवन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ट्वीट में सरकार के घटिया इंतजामों का विवरण दिया है।

उन्होंने "एक्स" पर लिखा:

डॉ. मनमोहन सिंह का स्टेट फ्यूनरल असम्मान एवं कुपबंधन का घटिया प्रदर्शन था।

– दिल्ली दूरदर्शन के अलावा, अन्य किसी समाचार एजेंसी को वहाँ आने की अनुमति नहीं थी, डी.डी. का फोकस मोदी और शाह पर रहा तथा यदा-कदा डॉ. मनमोहन सिंह के परिवार को कवर किया गया।

– डॉ. सिंह के परिवार के लिये पहली पंक्ति में केवल 3 कुर्सिया रखी हुई थीं। कांग्रेस नेताओं को उनकी पुत्रियों तथा अन्य परिजनों के लिये सीटों के लिये जोर देना पड़ा।

– जब राष्ट्र ध्वज स्व. प्रधानमंत्री की विधवा को दिया गया तथा जब तोपों की सलामी दी जा रही थी, तब प्रधानमंत्री तथा मंत्रीगण खड़े तक नहीं हुये।

– चिता के चारों तरफ सिंह के परिवार को यथेष्ट जगह नहीं दी गई थी, क्योंकि एक तरफ की जगह सैनिकों से घिरी हुई थी।

– जनता को बाहर ही रोक दिया गया था, वह बाहर से ही अंत्येष्टि के स्थान को देख पा रही थी।

– अमित शाह के मोटर काफिला से शव-यात्रा अवरुद्ध हो गई थी, सिंह के परिजनों की कारें बाहर ही रहीं। द्वार बंद कर दिया गया था, सिंह के परिजनों को ढूढ़ना पड़ा तथा अंदर लाना पड़ा।

– सिंह के अंतिम संस्कार को सम्पन्न करने वाले उनके नाती-नातिनों को चिता तक पहुँचने के लिये धक्का-मुक्की सहनी पड़ी।

–राजनयिकों को और कहीं बिठाया गया था तथा वे दिखाई नहीं दे रहे थे। यह बात आघात पहुँचाने वाली थी कि प्रधानमंत्री उस समय भी खड़े नहीं हुये, जब भूटान नरेश खड़े हुये थे।

– पूरा श्मशान बहुत तंग था तथा व्यवस्था बहुत खराब थी, बहुत से लोगों को शवयात्रा में जगह ही नहीं मिली।

इतने महान राजनेता के प्रति ऐसा लज्जाजनक तौर तरीका सरकार की प्राथमिकताओं तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसके सम्मान के अभाव को दर्शाता है। डॉ. सिंह गरिमा के हकदार थे, ऐसे शर्मनाक प्रदर्शन के नहीं।

अधिकांश मीडिया को बाहर ही रखा गया तथा सारे टी.वी. चैनलों ने दूरदर्शन से ही सामग्री ली, जिसका पूरा फोकस नरेन्द्र मोदी पर था। कई राजनेता, जो अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने फूल और मालाएं लेकर आये थे, बाहर ही रोक दिये गये, उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। दोनों पार्टियों के बीच तू-तू, मैं-मैं चलती रहने की आशा की जा रही है। डॉ. सिंह की अंत्येष्टि वाले दिन हुई सुधांशु त्रिवेदी की प्रैस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही कुरुचिपूर्ण एवं निम्नस्तर की माना जा रहा है।

सरकार ने कांग्रेस के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मनमोहन सिंह के अन्तर्राष्ट्रीय कद, उनकी महान उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार को उनके अंतिम संस्कार के लिए एक उपयुक्त स्थान क्यों नहीं मिला। यह और कुछ नहीं बल्कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का अपमान है।" शिरोमणि अकाली दल, सपा और आम आदमी पार्टी ने भी यही बात कही।

लोकसभा सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर डॉ. सिंह का परिवार ऐसा चाहता था तो बात अलग है वरना उनका अंतिम संस्कार वहां किया जाना चाहिए था जहां अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों का हुआ है।

सोशल मीडिया पोस्ट में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि, "चौंकाने वाला और अविश्वसनीय। यह अत्यंत निंदनीय है कि केन्द्र सरकार ने डॉ. मनमोहन सिंह के परिवार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है वे अत्यंत प्रतिष्ठित नेता का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करे जहां राष्ट्र के लिए उनकी अभूतपूर्व सेवाओं की याद में एक उपयुक्त और एतिहासिक स्मारक बनाया जा सके। यह स्थान राजघाट होना चाहिए और यह अतीत में अपनाई गई स्थापित प्रथा के अनुरुप होगा।" उन्होंने कहा, "यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार उस महान नेता का ऐसा अनादर क्यों कर रही है। डॉ. सिंह सिख समुदाय के एकमात्र नेता है जो प्रधानमंत्री बने।

अभी तक यह तय हुआ है कि अंतिम संस्कार आम जनता के लिए बने निगमबोध श्मशान घाट में होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के अन्तर्राष्ट्रीय कद के प्रति भाजपा इतनी ज्यादा पक्षपाती क्यों है कि उनका असम्मान करने पर उतर आई है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908